sweeper has been exclusively deployed to maintain these public conveniences.

Release of funds for Indira Gandhi Canal Project

1749. SHRI B. L. PANWAR: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the revised Defence share of Rs. 18 .71 crores on account of the cost of Indira Gandhi Canal—Jodhpur Drink:ng Water Supply Scheme accepted by the Central Government has been released and sent to State Government of Rajasthan;

(b) if not, by when it is likely to be sent; and

(c) by when the Jodhpur Drinking; Water Supply Scheme is to be completed and the Himalayan Water Board would reach Jodhpur?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Ministry of Defence has sanctioned their revised share of Rs. 18.71 crores on account of the cost of the Jodhpur Lift Canal Project form the Indira Gandhi Nahar Project, out of which Rs. 8.83 crores has been released upto March, 1991.

(b) The balance amount of Rs. 9.88 crores will be released by the Minisiry of Defence Proportionately as per the progress of the project.

(c) The Government of Rajasthan has intimated that though the project is scheduled to be completed by December, 1993, the date of completion is likely to be extended.

केप्टाफोल के उत्पादन पर रोक

1750. श्री भंवर लाल पंवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केप्टाफोल के उत्पादन तथा उसके प्रयोग पर रोक लगाने सम्बन्धी मामले की जांच के लिये एक विशेष समिति का गठन किया है ; यदि हां, तो कब तथा इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ख) क्या समिति ने इस समय तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सरकार ने कीटनाशकों, जिन पर दूसरे देशों में रोक लगा दिया गया है या जिनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, की समीक्षा के लिए डा. एस. एन. बैनर्जी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। प्रारम्भ में समिति का गठन दो वर्षों के लिए 14 अगस्त, 1984 को किया गया था, जिसकी अवधि दो-बार वार्षिक आधार पर क्रमश: 14 अक्तूबर, 1986 तथा 7 अक्तूबर, 1989 को बढ़ा दी गई थी ? । इस समिति द्वारा कैप्टाफोल कीटनाशक की समीक्षा की गई थी । समिति का गठन सलंग्न है।

(ख) समिति ने केप्टाफोल पर दिसम्बर 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था । सरकार ने केप्टाफोल को सीड-ड्रेसर के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है । पूर्ण विकास के रूप में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है ।